© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 08 , Issue : 02 | April - June 2021

शिक्षा में भारतीयता : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में

डॉ अमित कुमार जायसवाल
एसोसियेट प्रोफेसर (बी. एड. विभाग)
गवर्नमेंट पीजी कालेज, कोटद्वार , उत्तराखंड
ई-मेल –jaiswalamit1318@gmail.com

सारांशिका

लम्बे इंतजार और विचार-विमर्श के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को भारत सरकार द्वारा लाया गया है, जो भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक स्वागत योग्य कदम है. वास्तव में, स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 70 वर्षों के बाद तक हम भारत की शिक्षा नीति को भारत की प्रकृति, संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप बनाने में विफल रहे हैं. ऐसे में, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कोई शिक्षा नीति बनी है, जिसमें समग्रता में भारतीयता का समावेशन देखा जा सकता है. इस दृष्टि से 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' स्वयं में अद्वितीय है. 'नई शिक्षा नीति-2020' में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनके व्यावहारिक अनुप्रयोग से भारत की शिक्षा को एक नया स्पर्श मिलेगा, जिसके बल पर हम भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु के पद पर आसीन करने की दिशा में अग्रसर होंगे.

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, भारतीयता, शिक्षा, समावेशन

भारतीयकरण' का अर्थ है- जीवन के विविध क्षेत्रों में भारतीयता का पुनःप्रतिष्ठा। 'भारतीयता' शब्द 'भारतीय' विशेषण में 'ता' प्रत्यय लगाकर बनाया गया है जो संज्ञा (भाववाचक संज्ञा) रूप में परिणत हो जाता है। भारतीय का अर्थ है - भारत से सम्बन्धित। भारतीयता से तात्पर्य उस विचार या भाव से है जिसमें भारत से जुड़ने का बोध होता हो या भारतीय तत्वों की झलक हो या जो भारतीय संस्कृति से संबंधित हो। भारतीयता का प्रयोग राष्ट्रीयता को व्यक्त करने के लिए भी होता है। भारतीयता के अनिवार्य तत्व हैं - भारतीय भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा एवं संस्कृति। इसके अतिरिक्त अंतःकरण की शुचिता (आन्तरिक व बाह्य शुचिता) तथा सतत सात्विकता पूर्ण आनन्दमयता भी भारतीयता के अनिवार्य तत्त्व हैं। भारतीय जीवन मूल्यों से निष्ठापूर्वक जीना तथा उनकी सतत रक्षा ही सच्ची भारतीयता की कसौटी है। संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य (उदारता), रचनात्मकता, सह-अस्तित्व, बन्धुत्व आदि प्रमुख भारतीय जीवन मूल्य हैं।

भारतीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत महान प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा की जाती है । भारतीयकरण एक पुनःजगरण आन्दोलन है । यह आन्दोलन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में स्वदेशी पर अत्यधिक बल देता है। यह आन्दोलन भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित करने में कार्यरत है । यह आंदोलन मानवतावाद तथा भारतीय राष्ट्रीयतावाद पर बल देता है । यह आन्दोलन हिन्दी, संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं की रक्षा करता है ।

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 08 , Issue : 02 | April - June 2021

भारतीयता की प्रकृति से तात्पर्य उन मान बिंदुओं से है जिनकी उपस्थिति में भारतीयता का आभास होता है। भारतीयता निम्नांकित बिंदुओं/अवधारणाओं से प्रकट होती है-

वसुधैव कटुम्बकम् की अवधारणा : संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की विशाल भावना भारतीयता में समाविष्ट हैं।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

(यह मेरा है, यह पराया है, ऐसे विचार तुच्छ या निम्न कोटि के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति समस्त संसार को ही कुटुम्ब मानते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम का मन विश्वबंधुत्व की शिक्षा देता है।)

विश्व कल्याण की अवधारणा :

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भाग्भवेत॥

भारतीय वाङ्मय में सदा सबके कल्याण की कामना की गई है। उसे ही सार्वभौम मानवधर्म माना गया है। मार्कण्डेय पुराण में सभी प्राणियों के कल्याण की बात की गई है। सभी प्राणी प्रसन्न रहें। किसी भी प्राणी को कोई व्याधि या मानसिक व्यथा न हो। सभी कर्मों से सिद्ध हों। सभी प्राणियों को अपना तथा अपने पुत्रों के हित के समान वर्ताव करें।

त्याग की भावना : ईशावास्योपनिषद के प्रथम श्लोक में ही भारतीयता में त्याग की भावना स्पष्ट है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत।

तेन त्यकतेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम ॥

अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत है। यह समस्तम ईश्वर में व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगते रहो। उसमें आसक्त नहीं हों क्योंकि धन भोग्य किसका है अर्थात् किसी का भी नहीं। यह राजा से लेकर रंक तक त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। भारत में राजा जनक से राजा हर्ष तक यही प्रेरणा मिलती है।

वितरण के प्रति दृष्टि :

शत् हस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।

कृतस्य कार्यऽस्य चेह स्फार्ति समावह ॥ - अथर्ववेद

मानव जीवन की गुणवत्ता के संवर्द्धन तथा सामाजिक व आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा एक मूलभूत तत्त्व है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि पूंजीगत एवं प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में मानवीय संसाधन प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास के चरित्र तथा गति को अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास के निष्क्रिय तत्त्व हैं जबकि मानवीय संसाधन एक सक्रिय तत्त्व है। मानवीय संसाधन ही पूंजी का संचय करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संगठनों का निर्माण करते हैं तथा राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरह से जो राष्ट्र अपने नागरिकों में निपुणताओं तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करने तथा उपयोग करने में असमर्थ रहते हैं वे कुछ भी विकास करने में सफल नहीं हो सकते।

विश्व बैंक रिपोर्ट 2007 में कहा गया है कि जो विकासशील देश अपनी युवा शक्ति (12-24 वर्ष) की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर विनियोग करते हैं, वहां अच्छी विकास की दर तथा घटती निर्धनता प्राप्त की जा सकती है।

शिक्षा आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्पादकता एवं औद्योगिक किस्म को बढ़ाने, सूचना तंत्र तथा जैविक तकनीक क्षेत्र को गति देने, विनिर्मित एवं सेवा निर्यात क्षेत्र के उत्तेजित विस्तार करने, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने, घरेलू स्थिरता तथा शासन की गुणवत्ता के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा की पहुंच तथा गुणवत्त पूर्ण शिक्षा की पूर्व एवं आवश्यक शर्त है।

नवीन शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समग्रता की दृष्टि का परिचय दिया गया है. वास्तव में, समग्रता की दृष्टि ही सही अर्थों में भारतीय दृष्टि है. इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है कि 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के स्थान पर अब 'शिक्षा मंत्रालय' की संकल्पना प्रस्तुत की गई है. सच कहें तो मनुष्य को संसाधन मात्र मान लेना भारतीय दृष्टि नहीं है. भारतीय दृष्टि में मनुष्य एक स्वतंत्रचेत्ता प्राणी है, जो संवेदनशील है और केवल उत्पादन का साधन मात्र नहीं है. इसी प्रकार परंपरागत ज्ञान के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यवसाय केन्द्रित विषयों को भी समान और संतुलित महत्व दिया गया है. अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा.

भारतीय परंपरा में शिक्षा और समाज का गहरा संबंध रहा है. समाज के सहयोग से ही भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की एक समृद्ध परंपरा देखी गई है. इस बात का नीति में स्पष्ट समावेशन किया गया है. विद्यालय और समाज के अंतःसंबंधों को इस नीति ने गहराई से पुनर्स्थापित करते हुए शिक्षा को समाज की जिम्मेदारी के रूप में रेखांकित किया है. यह शिक्षा में भारतीयता के अनुगूंज की तरह है.

'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है – मातृभाषा में शिक्षा. दुनिया के सारे भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा सर्वाधिक वैज्ञानिक पद्धति है. फिर भी, हम इतने वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में विद्यार्थियों को अंग्रेजी थोपते आ रहे हैं. इस दृष्टि से मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा नीति का सबसे सुंदर पक्ष है. इससे भारतीय भाषाओं में शिक्षा का द्वार खुलेगा. कोठारी आयोग से लेकर कई आयोगों और समितियों ने अपनी सिफारिशों में (जी.डी.पी.) सकल घरेलू उत्पाद का 6%

शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की बातें कही थी, परंतु उसे मूर्त रूप इसी शिक्षा नीति में दिया गया है. सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जी.डी.पी. का 6% शिक्षा में लगाया जाए जो अभी 4.43% है.

परंपरागत भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी शिक्षा का अच्छा सामंजस्य इस नवीन शिक्षा नीति में दृष्टिगोचर होता है. ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) भी गठित किया जा रहा है. कक्षा-6 के बाद से ही वोकेशनल पाठ्यक्रमों को जोड़ने की बात कही गई है. बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा. कहीं- न- कहीं यह नीति विद्यार्थियों को रटंत विद्या से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है. शिक्षा के सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यावहारिक पक्षों पर बल दिया गया है. वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी. विद्यालयी शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी, जिससे वो जिस क्षेत्र में काम शुरु करना चाहेगा, कर सकेगा. शिक्षकों का सम्यक प्रशिक्षण किसी भी शिक्षा-व्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है. इस शिक्षा-नीति में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर काफी सूक्ष्मता से विचार कर निर्णय लिया गया है.

उच्च शिक्षा के दो आधार बिंदु होते हैं – शिक्षण और शोध. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और शोध दोनों पर संतुलित बल दिया गया है. गुणवत्तापूर्ण शोध-कार्य, राष्ट्र, समाज और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो – इस दृष्टि से 'राष्ट्रीय शोध-प्रतिष्ठान' का प्रावधान है. यह भारत में शोध-कार्य हेतु एक नियामक संस्था होगी, जिसमें विज्ञान के साथ-साथ समाज विज्ञान, कला व मानविकी के विषयों से संबंधित शोध-कार्यों को जोड़ा गया है. यह शिक्षा नीति उच्च शिक्षा में बहुअनुशासनिकता एवं समग्र शिक्षा के मूल्यों को पोषित करते हुए भविष्य में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल में ज्ञान की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करेगी.

भारत जैसे बहुभाषी देश में सभी भारतीय भाषाओं का विकास आवश्यक मानते हुए यह नीति त्रिभाषा-सूत्र को अंगीकार कर रही है, जो प्रशंसनीय है.

कला और विज्ञान के अनुशासनों के मध्य संरचनागत विभेदों को समाप्त करते हुए पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर गतिविधियों, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं को सीखने के सहज और सुलभ पद्धतियों को उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के पदानुक्रम और बाधाओं को समाप्त करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहयोगी सिद्ध होगी. ऑनलाइन शिक्षा पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने काफी सूक्ष्मतापूर्वक विचार कर कई प्रावधान किए गए हैं. जैसे -आधारभूत डिजिटल संरचनाओं का प्रावधान, शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षण हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन इत्यादि. कोरोना काल में जो एक वैश्विक परिस्थिति चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई है, वैसे में ऑनलाइन शिक्षण का प्रावधान एक दूरदर्शी कदम कहा जाएगा.

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की स्वायत्तता पर भी काफी बल दिया गया है. प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वतंत्र समितियों द्वारा पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ शासित किया जाना है. पाठ्यक्रम को लचीला बनाने का प्रावधान है ताकि विद्यार्थी अपने सीखने की गति और कार्यक्रमों का चयन कर सके और इस

प्रकार जीवन में अपनी प्रतिभा और रूचि के अनुसार अपने रास्ते चुन सकें. शिक्षा नीति का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर न खो दे.

समग्रता में कहा जाए तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की शिक्षा में भारतीयता का सही अर्थों में प्रादुर्भाव हुआ है. सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा के मध्य, भौतिकता और आध्यात्मिकता के मध्य, परंपरागत मूल्यबोध और आधुनिक तकनीक के मध्य समन्वय की एक सुंदर चेष्टा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखी जा सकती है. आवश्यकता है, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सम्यक तरीके से व्यावहारिक धरातल पर उतारने की.

शिक्षा प्रणाली का किसी भी देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जिस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए थी, उसका हमारे देश में नितांत अभाव महसूस किया जाता रहा है। शायद, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने शिक्षा नीति बनाने के बारे में कम चिन्तन किया। इसी कारण आज की नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी देने से वंचित किया जा रहा है। यहां यह बताना आवश्यक है कि इतिहास कोई सौ या दो सौ सालों में नहीं बनते। जहां तक भारत के दो सौ सालों के इतिहास की बात है तो इस दौरान भारत परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा रहा था। इसलिए स्वाभाविक है कि उस कालखंड का इतिहास हमारा मूल इतिहास नहीं कहा जा सकता। अगर हमें भारत के इतिहास का अध्ययन करना है तो उस कालखंड में जाना होगा, जब भारत पर किसी विदेशी का शासन नहीं था। क्या आज यह इतिहास कोई जानता है, ... बिलकुल नहीं।

मार्क्सवादी चिन्तक मैकाले ने शिक्षा के लिए जिस नीति को समाज के लिए प्रस्तुत किया, उसका हमारी सरकारों ने आंख बंद करके समर्थन किया। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, इसका चिन्तन नहीं किया गया। नतीजतन, आज सरेआम कहीं-कहीं भारत माता को डायन कहने के स्वर सुनाई देते हैं, तो कहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वालों का जमावड़ा दिखाई देता है। आज जो वातावरण देश में दिखाई देता है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपनी मूल धारा से विमुख होते दिखाई दे रहे हैं। हमें विदेशी गुलामी के बाद जिस प्रकार का भारत मिला, हमारी सरकारों ने वैसे ही स्वरुप में उसे स्वीकार कर लिया।

देश में अभी जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह सांस्कृतिक मानकों के हिसाब से भारतीय नीति के अनुरूप नहीं कही जा सकती। विश्व के प्रायः सभी देशों में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वह उस देश के मूल भाव को संवर्धित करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा शिक्षा का मूल यह होना चाहिए कि उसमें उस देश का मूल संस्कार परिलक्षित हो। हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि जिन महापुरुषों ने देश की सुरक्षा को अपने कर्तव्य का मूल समझा था, आज वे महापुरुष राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं। हमने महापुरुषों को भी राजनीतिक दलीय आधार पर बांटकर रख दिया। हमारे देश के महापुरुषों में शामिल कई ऐसे हैं, जिनकी वाणी भारतीयता का बोध कराती थी। यानी उनकी वाणी भारत की आवाज होती थी। लेकिन आज भारत की आवाज को मुखरित करने वाले उन महापुरुषों को हमारी सरकारें लगभग भूलती जा रही हैं। अंग्रेज जिनको सत्ता सौंप कर गए, उनका ही बोलबाला देश में सुना जाता है। हमारे देश की कुछ किताबों में छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी के

रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब हम भारत की रक्षा करने वाले वीर शिवाजी को आतंकवादी के रूप में पढ़ेंगे, तब हमारी युवा पीढ़ी से हम किस प्रकार से यह अपेक्षा करें कि वे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति सजग रहें। इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया, उनको पूरा सम्मान भी नहीं मिल रहा। उनको इतिहास की किताबों में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई घटना के बाद एक बार फिर से भारतीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता आन पड़ी है। शिक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली, किताबी शिक्षा तो दूसरी व्यावहारिक शिक्षा। किताबी शिक्षा के लिए आज भारत के शिक्षालय समर्पित दिखाई देते हैं। देश का हर निजी विद्यालय लगभग विदेशी शिक्षा से प्रभावित होकर अपने संस्थान में विदेश से प्रेरित शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। जिसमें अंग्रेजी भाषा की प्रधानता तो है ही, साथ ही अंग्रेजी संस्कारों की बहुलता का दर्शन कराया जाता है। कौन नहीं जानता देश के ईसाई शिक्षा संस्थानों को, जिसमें प्राय: बच्चों को भारतीयता से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। कई शिक्षा संस्थानों में इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि विद्यार्थियों को केवल ईसाई धर्म ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। चर्च के रूप में संचालित किए जाने वाले ये ईसाई शिक्षा केंद्र आज भारत को नकारने जैसे ही कार्य करते दिखाई देते हैं। वहां भारत माता की जय बोलने पर प्रतिबंध होता है। कई बार विद्यार्थियों को भारत माता की जय बोलने पर दंडित किया जाता है। जिस शिक्षा के संस्थानों में उस देश के संस्कार नहीं होते, उस संस्थान की शिक्षा उस देश के विरोध में की गई कार्रवाई का ही हिस्सा माना जाता है।

वर्तमान में हमारे देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों की हालत का अध्ययन करने से पता चलता है कि इन संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति लगातार गिरती जा रही है। इसके पीछे का मूल कारण हमारी वर्तमान शिक्षा नीति है। वास्तव में शिक्षा के स्वरूप में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। समूचे देश में शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। यह भारत देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों द्वारा शिक्षा के भारतीयकरण को भगवाकरण का नाम दे दिया जाता है। भगवाकरण के नाम पर विरोध करने वाले वे ही लोग हैं, जो कथित बुद्धिजीवी बनकर देश की सरकारी सुविधाओं का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। भारतीयकरण शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि भारत से जुड़ी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाए। भारतीय मूल्यों के साथ रोजगारपरक शिक्षा सभी को देनी होगी, तभी देश से बेरोजगारी जैसी समस्या का भी निर्मूलन हो सकेगा। साथ में अन्य क्षेत्रों में भी विकास तेजी से नजर आएगा। हमें पहले यह समझना होगा कि शिक्षा किसलिए जरूरी है? क्या केवल साक्षर होने या नौकरी के लिए पढ़ाई की जानी चाहिए अथवा इसके और भी गहरे मायने हैं? विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय वह केंद्र होते हैं जहां विद्यार्थी को वैचारिक स्तर पर गढ़ने का कार्य किया जाता है। सही बात यही है कि यदि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के सभी प्रमुख अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और गैर शैक्षणिक कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से ईमानदार होकर करने लगें तो भारत में शिक्षा की साख पर उत्पन्न होते खतरे से आसानी से निपटा जा सकता है। जितना संभव हो उतना अधिक आर्थिक व अन्य सहयोग देश की शिक्षण संस्थाओं को दिया जाए।

पहले भारत की शिक्षा के प्रति विश्व के सभी देशों में एक आदर भाव था। विश्व के कई देशों के नागरिक भारत के शिक्षालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन आज के युवा विदेश में पढ़ाई करने के लिए उतावले

होते जा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा नीति का दुष्परिणाम ही कहा जाएगा। इस सबका परिणाम यह है कि भारतीय विद्यार्थियों में उत्तम किस्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के देशों के बीच आज भी भारत में उच्च शिक्षा में सबसे कम जनसंख्यात्मक अनुपात के हिसाब से प्रवेश होते हैं। उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बाद भी स्थिति में अभी तक बहुत सुधार नहीं आ पाया है। जैसी शिक्षा दी जाएगी, देश का मानस उसी प्रकार का बनता जाएगा। इसलिए समाज को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे असली भारत का निर्माण हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

I. कोठारी, अतुल (2020). शिक्षा में भारतीयता एवं विमर्श : प्रभात प्रकाशन
II. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf लिंक से लिया गया |
III. https://www.sites.google.com/site/brandhindi/mantra-om-sarve-bhavantu-sukhinah-mantra#:~:text=Om%20Sarve%20Bhavantu%20Sukhinaha)&text=
IV. https://upanishads.org.in/upanishads/1/1
V. http://literature.awgp.org/akhandjyoti/1995/April/v2.6